प्रेषक,

जयदेव सिंह, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2013

विषय— मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त मा० मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशगण के मत्तों/सुविधाओं में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0—153/XXXVI(1)/ 09—308 एक/02 दिनांक 18.06.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशगण के नित प्रतिदिन के आकिस्मक कार्यों के सम्पादन के लिए की जाने वाली सेवाओं हेतु उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.06.2009 में पूर्व निर्धारित भत्तों के स्थान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिमाह निम्नांकित विवरणानुसार व्यय वहन करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त मा० मुख्य न्यायाधीश के लिए

सेवक भत्ता – रू० 10,000 / –

2. मिनिस्ट्रीयल असिस्टेन्स भत्ता — <u>रू० 10,000/-</u> **कुल ~ रू० 20,000/-**

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त मा० न्यायाधीश के लिए

सेवक भत्ता – रू० 8,000 / –

2. मिनिस्ट्रीयल असिस्टेन्स भत्ता — <u>रू० 7,000 / -</u> कुल **रू० 15,000 / -**

- 2- उपरोक्तानुसार सेवक तथा मिनिस्ट्रीरियल असिस्टेन्स भत्ता:-
- (अ) मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में मूलतः नियुक्त एवं मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मा० मुख्य न्यायाधीश / मा० न्यायाधीश को अनुमन्य होंगे।

- (ब) मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में मूलतः नियुक्त एवं किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित एवं ऐसे अन्य उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० न्यायाधीश को उक्त भत्ते मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय अथवा सेवानिवृत्ति वाले उच्च न्यायालय से प्राप्त करने का विकल्प होगा।
- (स) सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण/आयोग अथवा पारिश्रमिक वाले किसी अन्य पद पर कार्यरत मा० मुख्य न्यायाधीश/मा० न्यायाधीश को ऐसी कार्यावधि के दौरान भत्ते अनुमन्य न होंगे।
- 3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0—04 के अधीन लेखाशीर्षक "2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेत्तर—00—102—उच्च न्यायालय—03—उच्च न्यायालय—00—02 मजदूरी" के नामें डाला जायेगा।
- 4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—175NP/XXVII(5)/2013-14 दिनांक 24.12.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय (जयदेव सिंह) प्रमुख सचिव

संख्या- 226(1)/XXXVI(1)/2013-308 एक/02

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3. वित्त अनुभाग-5/गार्ड फाईल/एन.आई.सी.।

आज्ञा से

(राकेश कुमार सिंह) संयुक्त सचिव